जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौनसिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 14 संख्याः 228 प्रभात हिण्डौन सिटी, रविवार 19 जून, 2022 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 8 मूल्य 2.00 रु.

माइग्रेट करने वाले टर्टल असल में नहीं जानते की वो कहां जा रहे हैं। हाल ही में एक शोध में पता लगा है कि हॉक्सबिल टर्टल छोटी सी दूरी के लिए भी चक्करदार रास्ते का प्रयोग करते हैं। एक बार एक टर्टन ने मात्र 176 किलोमीटर दूर स्थित एक द्वीप तक पहुंचने के लिए 1306 किलोमीटर दूरी तय की। वैज्ञानिकों की एक अन्तर्राष्ट्रीय टीम ने हॉक्सबिल टर्टल की गतिविधियों को उस समय मैप किया, जब वो चागस द्वीप समूह के अपने प्रजनन क्षेत्र से भोजन की तलाश में निकले। चागस द्वीप समूह और उनके भोजन के ठिकाने दोनों ही हिंद महासागर में हैं। अध्ययन में पाया गया कि, टर्टल ने छोटी दूरी तक माइग्रेट करने के लिए घुमावदार रास्ता तय किया, जिससे यह बात समझ में आती है कि खुले समुद्र में उनकी नैविगेशनल सूझबूझ काफी कम होती है। शोध में पाया गया कि एक टर्टल ने अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए 7 गुना ज्यादा दूरी तय की। टीम ने नैस्टिंग पूर्ण कर चुके 22 हॉक्सबिल टर्टल के टैग लगाकर उन्हें ट्रैक किया। डीकिन युनिवर्सिटी के वैज्ञानिक और प्रथम शोध लेखक, प्रोफेसर ग्रेअम हेज़ ने कहा कि ''अगर वे ''परफैक्ट नैवीगेटर्स'' होते तो अपने प्राकृतिक आवास से भोजन स्थल तक जाने का सीधा रास्ता लेते।'' उन्होंने कहा, ''हम जिन टर्टल को ट्रैक कर रहे थे उन्होंने 4-5 महीनों से कुछ भी नहीं खाया भी नहीं था।'' पूर्व के एक शोध में कहा गया था कि, कछुए संभवतया अपने जन्म स्थल की मैग्नैटिक फील्ड को पहचानते हैं और बाद में अण्डे देने वहीं लौटते हैं और संभवतया वो पृथ्वी के चुम्बकीय फील्ड में परिवर्तन का भी पता लगा लेते हैं जिसकी मदद से समुद्र में नैविगेशन करते हैं। हेज़ ने कहा, ''नए शोध का सुझाव था कि, टर्टल जियोमैग्नैटिक नक्शे का उपयोग ज़रुर कर रहे हैं लेकिन उनका तरीका सुघड़ नहीं है। इसलिए टर्टल एकदम सीधे रास्ते पर नहीं जा पाते बल्कि लम्बा रास्ता चुनते हैं।'' हेज़ ने कहा, ''दूसरी तरफ, ग्रीन टर्टल 5000 किलोमीटर तक माइग्रेशन करते हैं, वे हिंदमहासागर को पार कर अफ्रीका के तट तक जाते हैं।'' नई रिसर्च कहती है कि, टर्टल की जिओमैग्नैटिक मैप समझ इतनी अच्छी नहीं होती कि वे अपनी मंज़िल का पता लगा सकें। हालांकि, मंज़िल के करीब होने पर वे गंध और लैण्ड मार्क की स्मृति का इस्तेमाल करके वहाँ पहुँच जाते हैं।

सरकार ने ''अग्निपथ'' भर्ती प्रोग्राम पर अडिग रहने का इरादा जताया

पर प्रदर्शनकारियों पर ठण्डे छीटें भी डाले, अग्निवीरों को सैन्ट्रल फोर्सेज़ में 10 प्रतिशत आरक्षण देना स्वीकार किया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 जून। नई सैन्य भर्ती ''अग्निपथ'' योजना के खिलाफ हो रहे विरोध-प्रदर्शन के आठ राज्यों में फैल जाने के फलस्वरूप, सरकार ने आज युवाओं के आक्रोश को कम करने के लिए दिये गये प्रलोभन के अन्तर्गत घोषणा कर दी कि ''अग्निवीरों'' को सैन्ट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज़ (सी.ए.पी.एफ.) तथा असम राइफल्स में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा।

ऐसा लगता है कि सरकार नर्म रुख अपनाने के मूड में नहीं है तथा विपक्ष की माँग या अपील को तवज्जो देने के लिये भी तैयार नहीं है। आम जनता में बन चुकी अपनी खराब छवि को बचाने तथा बनाये रखने की खातिर, जनमत या विरोध के आगे नहीं झुकने की अपनी नीति पर चलते हुये, मोदी सरकार अपनी घोषित अग्निपथ योजना पर अड़ी हुई है। यह अलग बात है कि सरकार ने कुछ सुविधा जरूर प्रदान कर दी है।

बिहार, जहाँ विरोध प्रदर्शन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, में भाजपा के सहयोग से बनी गठबंधन सरकार को चलाने वाले जनता दल (यूनाइटेड) ने जहाँ केन्द्र सरकार से इस योजना पर पुनर्विचार करने के लिये कहा है, वहीं विपक्षी दल माँग कर रहे हैं कि इस योजना को वापस लिया जाये या फिर विशेषज्ञों तथा हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करने के बाद इसे कुछ समय बाद लॉन्च किया जाये।

- **सोनिया गांधी ने अग्निवीरों को भरोसा दिलाया कि, कांग्रेस अग्निपथ स्कीम वापस लिए जाने के लिये उनके साथ है।**
- **बिहार में भाजपा के साथ गठबंधन सरकार में शामिल जद (यू) ने भी अग्निपथ स्कीम पर पुनर्विचार करने के लिये दबाव बनाया।**
- **रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जरूर पुरज़ोर ढंग से कहा कि, यह स्कीम लागू करने से पहले पूर्व सैनिकों व सेना के वर्तमान अफसरों के साथ बैठकर काफी मंथन व सलाह मशविरा हुआ है।**
- **गृह मंत्रालय ने अर्द्ध सैनिक बलों में भर्ती के लिये निर्धारित आयु सीमा में अग्निवीरों के लिये तीन साल की रियायत देने का भी निर्णय लिया है।**
- **हरियाणा के महेन्द्रगढ़ रेलवे स्टेशन के अलावा पंजाब के लुधियाना स्टेशन पर भी प्रदर्शनकारियों ने काफी तोड़-फोड़ की।**
- **बिहार में प्रदर्शनकारियों ने लगभग एक दर्जन रेल गाड़ियों में आग लगायी।**

जे.डी. (यू.) प्रवक्ता के.सी. त्यागी ने कहा कि उनकी पार्टी इसे वापस लेने के लिये नहीं, बल्कि, व्यापक युवा-आक्रोश के चलते, इस पर पुनर्विचार करने के लिये कह रही है।

सरकार पर दबाव डालते हुये, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ आंदोलन कर रहे युवाओं को दिये एक संदेश में, उनसे अपील की कि वे शान्तिपूर्ण एवं अहिंसक विरोध करते रहें। उन्होंने कहा, ''कांग्रेस अपनी पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ी हैं तथा इस योजना को वापस कराने के लिये संघर्ष करती रहेंगी।'' ज्ञातव्य है कि सोनिया गांधी इस समय अस्पताल में भर्ती है तथा कोविड के बाद की अपनी तकलीफ से उबर रही हैं। विपक्ष की माँगों के प्रतिकार की कोशिश के अन्तर्गत, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जो बिहार के रहने वाले हैं, को सत्तारूढ़ दल ने यह कड़ा संदेश देने के लिये मैदान में उतार दिया है कि अग्निपथ के खिलाफ हो रहा आंदोलन गलत एवं भ्रामक जानकारी का नतीजा है। पासवान ने कहा कि इस योजना को तैयार किये जाने से पहले, पूर्व सैन्य अधिकारियों एवं पूर्व

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री ने गुजरात पर रेलवे प्रोजैक्ट्स की बारिश की

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 जून। प्रधानमंत्री ने आज अपने गृह राज्य गुजरात को 16 हजार करोड़ रूपयों की रेल परियोजनाओं की सौगात दी। गुजरात में आगामी नवम्बर माह में विधानसभा चुनाव होने हैं।

एन.डी.ए. सरकार ने संसद में अलग से रेल बजट प्रस्तुत करने की 92 वर्ष पुरानी प्रथा को वर्ष 2016 में तिलांजलि दे दी थी। तब यह तर्क दिया गया था कि सार्वजनिक परिवहन के इस साधन को पुरानी लोकलुभावन संस्कृति के जाल से मुक्त करने की आवश्यकता है। तब से लेकर अब छह वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों है। संसद में अलग से रेल बजट पेश करने की परम्परा खत्म कर रेल मंत्रियों से फोकस खत्म कर दिया गया है। अब प्रधानमंत्री सहित सशक्त राजनेता बड़ी रेल योजनाओं की घोषणा कर वाहवाही लूटते हैं खासकर चुनाव के मौसम में, जैसा यू.पी. में हुआ था।

प्रधानमंत्री ने जिन रेल प्रोजैक्ट्स की घोषणाएं की हैं, उनमें पालनपुर-मदार के डैडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नए 357 कि.मी. लम्बे खण्ड का शिलान्यास अहमदाबाद-बोटाद खण्ड की 166 कि.मी. लाइन का गेज परिवर्तन और 81 कि.मी. लम्बे पालनपुर-मीठा खण्ड का विद्युतीकरण शामिल है।

- **संसद में अलग से रेलवे बजट पेश होने की परम्परा खत्म होने से रेल मंत्री पर बजट के दौरान फोकस तो खत्म हुआ ही, साथ ही प्र.मंत्री व वरिष्ठ मंत्रियों को बड़े-बड़े रेलवे प्रोजैक्ट्स की घोषणा करने का सदाबहार मौका मिल गया।**
- **इस मौके का भरपूर फायदा उठाया जाता है चुनाव के मौसम में, जैसा कि यू.पी. के चुनाव के समय देखा गया था।**

सूरत में हाई स्पीड स्टेशन का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है, जबकि सूरत से गुजरने वाली प्रस्तावित मुम्बई-अहमदाबाद हाई स्पीड लाइन के लिए अगस्त माह में 50 कि.मी. लम्बी ट्रायल की योजना है।

संभावना है प्रधानमंत्री अपनी आगामी गुजरात यात्रा के दौरान इन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।

इस वर्ष की शुरूआत में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पूर्व एन.डी.ए. नेताओं ने इसी प्रकार की कुछ रेल परियोजनाओं की घोषणा की थी। इनमें पीलीभीत से शाहजहांपुर की 83 कि.मी. लम्बी लाइन का गेज परिवर्तन, उतरेलिया से रायबरेली तक 60 कि.मी. लम्बी नई रेल लाइन, गाजीपुर से अन्निहार की 40 कि.मी. लाइन और अयोध्या से वाराणसी का विद्युतीकरण प्रोजैक्ट शामिल था।

पूर्व के रेल मंत्री जहां फण्ड्स को लेकर जद्दोजहद करते थे और अपने निर्णयों के लिए तत्कालीन योनजा आयोग या वित्त मंत्रालय के प्रति जवाबदेह हुआ करते थे, वहीं अब रेल बजट की अलग व्यवस्था के अभाव में मंत्रालय का अपने व्यय पर बाह्य व आंतरिक नियंत्रण नहीं रह गया है और रेलवे की कायापलट करने का वादा भी पूरा नहीं हुआ है।

नया मीडिया सैटअप

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 जून। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा रणदीप सिंह सुरजेवाला की जगह पार्टी सांसद जयराम रमेश (68) को सोशल और डिजिटल मीडिया सहित संचार, प्रचार और मीडिया का प्रभारी बनाए जाने के बाद राजस्थान के सांसद पवन खेड़ा (53) को नए संचार विभाग में मीडिया और प्रचार का चेयरमैन बनाया गया है।

- **जयराम रमेश को कांग्रेस का मीडिया प्रभारी बनाया गया है तथा पवन खेड़ा डिजिटल मीडिया का कामकाज देखेंगे।**

दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले खेड़ा उस वक्त पार्टी प्रवक्ता थे जब सुरजेवाला संचार विभाग के प्रमुख थे। हाल ही हुए राज्यसभा चुनावों में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मंत्री हैं या सेल्समैन?

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 जून। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने शनिवार को प्रधानमंत्री की भर्त्सना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने मंत्रियों का कद घटाकर उन्हें ''अग्निपथ'' भर्ती योजना का प्रचार करने में उसी तरह से लगा दिया है, जैसे कि कोई सेल्समैन किसी रेलवे स्टेशन के बाहर चूहे मारने की दवा का फॉर्मूला बेचता है।

कन्हैया कुमार अब कांग्रेस में हैं और ए.आई.सी.सी. के नए मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा और पार्टी सांसद प्रमोद तिवारी के साथ यहां ए.आई.सी.सी. मुख्यालय पर एक संयुक्त प्रैस कांफ्रैंस को संबोधित कर रहे थे। प्रैस कांफ्रैंस का उद्देश्य सरकार पर यह दबाव डालना था कि वह बिना किसी विचार-विमर्श के लागू की गई इस योजना को वापस ले।

उक्त तीनों नेताओं ने इस स्कीम के खिलाफ आंदोलनरत युवाओं, खासकर बिहार के युवाओं से अपील की कि वे शांत और अहिंसक रहे, तभी उनका संघर्ष सफल होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस पर चुप्पी साध रखी है कि सेना में प्रति वर्ष रिक्त होने वाले 55 हजार पदों को नियमित प्रक्रिया से ना भरे जाने के क्या कारण हैं।

खेड़ा ने जोर देकर कहा कि सरकार बात सेना का असैन्यीकरण कर 75 प्रतिशत प्रशिक्षित सैनिकों को पुनः सार्वजनिक जीवन में लाकर समाज का सैन्यीकरण करना है।

प्रमोद तिवारी ने इस स्कीम को ''नो रैंक, नो पेंशन, ओनली टैंशन विद्आउट डॉयरैक्शन'' की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बात को लेकर अधिक

- **जवाहर लाल नेहरू युनिवर्सिटी स्टूडैंट यूनियन के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने प्र.मंत्री मोदी पर कटाक्ष किया।**
- **कन्हैया कुमार के अनुसार केन्द्रीय मंत्री अब ठीक उसी तरह अग्निपथ स्कीम की मार्केटिंग करने में व्यस्त हैं, जैसे स्टेशन के बाहर ठेले वाले चूहे मारने की दवा की मार्केटिंग में मशगूल रहते हैं।**

सशस्त्र सेनाओं में आर.एस.एस. की घुसपैठ कराने के लिए अग्निपथ योजना लायी है और इसके लिए ऐसे 25 प्रतिशत की पहचान की गई है जो उसकी विचारधारा का अनुसरण करते हैं। उन्होंने कहा कि इससे भी अधिक गंभीर चिंतित है कि सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करीब 75 प्रतिशत युवा पुनः समाज में आएंगे, जिससे खुले आम घूमने वाले सशस्त्र लोगों की गैंग्स बन सकती है। कन्हैया ने कहा कि मोदी के सेल्समैन लॉलीपॉप

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'होटल 17 लाख रूपए वापस लौटाए'

जयपुर, 18 जून (का.सं.)। राज्य उपभोक्ता आयोग ने अपने एक फैसले में कहा है कि वर पक्ष की ओर से विवाह से इन्कार करने पर शादी समारोह निरस्त होने की स्थिति वधु पक्ष के नियंत्रण के बाहर की है।

परिवाद में अधिवक्ता भूपेन्द्र पारीक ने आयोग को बताया कि परिवादी ने अपनी बेटी के 17 अप्रैल 2019 को शादी समारोह के लिए प्रतिवादी होटल से 9 फरवरी को एग्रीमेंट किया था। उसके पेटे परिवादी की ओर से 9 अप्रैल तक कुल बीस लाख रुपए होटल प्रबंधन को अदा किए गए। लेकिन वर पक्ष ने

- **वधु पक्ष ने शादी के लिए होटल वालों को 20 लाख रू. जमा कराये थे।**
- **उपभोक्ता आयोग ने कहा कि, शादी कैंसिल होना अकेले वधु पक्ष के नियंत्रण की बात नहीं, होटल 17 लाख रू. वापस लौटाये।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या ट्रम्प, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिये अब कभी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे?

अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमैंट ने ट्रम्प पर ऑफिशियली 6 जनवरी, 2021 को संसद व सत्ता के प्रशासनिक केन्द्र पर हमला करने व हिंसा फैलाने के लिये प्रेरित का आरोप लगाया है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 जून। यू.एस. डिपार्टमैंट ऑफ जस्टिस (डी.ओ.जी.) ने 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद पर हुए हमले को भड़काने, उसका समर्थन करने और वर्ष 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को बदलने को लेकर पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के खिलाफ अभियोग चलाया है। एक नए सर्वेक्षण के अनुसार डी.ओ.जी. के इस कदम का उन अधिकांश अमेरीकियों ने समर्थन किया है, जिनका मानना है कि इस हमले के संबंध में ट्रम्प के खिलाफ आपराधिक केस चलना चाहिए।

नैवीगेटर रिसर्च द्वारा किए गए एक सर्वे में पाया गया कि 54 प्रतिशत प्रतिभागी अमेरिकी संसद में हुए दंगे को लेकर पूर्व राष्ट्रपति पर अभियोग चलाने के डिपार्टमैंट ऑफ जस्टिस के विचार के समर्थन में थे, जबकि 37 प्रतिशत प्रतिभागियों ने इस सुझाव का विरोध किया।

सर्वेक्षण के डेटा बताते हैं कि रिपब्लिकन्स ही वह पक्षपाती ग्रुप है जिसके अधिकांश नेता और कार्यकर्ता यह नहीं चाहते कि अमेरिकी संसद भवन में हुए दंगों में ट्रम्प की भूमिका के लिए उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। ट्रम्प समर्थकों ने जब संसद भवन पर हमला किया था तब उसके अंदर मौजूद कांग्रेस सदस्य जो बाइडन की जीत को सत्यापित कर रहे थे।

करीब तीन चौथाई (71 प्रतिशत) रिपब्लिकन्स ने हमले में ट्रम्प की भूमिका को लेकर उनके विरूद्ध डी.ओ.जी. के आपराधिक आरोपों के खिलाफ विचार व्यक्त किए, जबकि 21 प्रतिशत ने इस विचार का समर्थन किया।

इसकी तुलना में 86 प्रतिशत डैमोक्रेट्स और 47 प्रतिशत निर्दलियों ने कहा कि संसद भवन में हुए दंगों को लेकर वे ट्रम्प पर अभियोग चलाने के समर्थन में हैं।

सर्वे के अनुसार पांच में से चार अश्वेत प्रतिभागियों (80 प्रतिशत) का भी मानना था कि ट्रम्प पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और 49 प्रतिशत श्वेत प्रतिभागियों, 58 प्रतिशत हिस्पैनिक वोटर्स तथआ 65 प्रतिशत एशियन अमेरिकन व पैसिफिक आईलैण्डर्स ने इस विचार का समर्थन किया।

- **54 प्रतिशत जनता ट्रम्प के खिलाफ मुकदमा चलाने के पक्ष में है।**
- **अगर यह आरोप सिद्ध हो जाता है तो, ट्रम्प को दोबारा राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं मिल पायेगी।**

नैवीगेटर रिसर्च ने गत 9 जून से 13 जून तक सर्वेक्षण किया था जिसमें 998 रजिस्टर्ड वोटर्स को शामिल किया गया था। नैवीगेटर रिसर्च स्वयं को आकर्षक प्रगतिशील संदेशों के वितरण और ज्वलंत मुद्दों पर पोलिंग का एक विश्वस्त स्त्रोत मानता है।

सर्वे में यह भी पाया गया कि रायशुमारी में शामिल 13 प्रतिशत डैमोक्रेट्स, ट्रम्प समर्थकों द्वारा 6 जनवरी को की गई कार्रवाई के समर्थन में थे और एक तिहाई (33 प्रतिशत) रिपब्लिकन्स का कहना था कि वे अपने कार्य को सही मानते हैं।

सर्वे में भाग लेने वाले अधिकांश विभिन्न आबादी समूहों ने कहा कि उन्होंने हाउस सलैक्ट कमेटी की लाइव हीयरिंग्स में 6 जनवरी के बारे में ''बहुत कुछ'' या ''कुछ'' सुना है।

रायशुमारी में शामिल कुल 64 प्रतिशत ने कहा कि वे संसद भवन हमले में कमेटी की जांच का समर्थन करते हैं। इसकी तुलना में 28 प्रतिशत ने कहा कि वे इसके विरोध में हैं।

जांच कार्रवाई को रिपब्लिकन्स का भी अच्छा-खासा समर्थन मिला है। सर्वे में शामिल हुए 40 प्रतिशत ने कहा कि वे इसके समर्थन में हैं, जबकि 51 प्रतिशत ने कहा कि वे इसके खिलाफ हैं।

यदि हाउस कमेटी ट्रम्प को दोषी मान लेती है तो क्या होगा? विश्लेषक तर्क देते हैं कि ऐसी स्थिति में ट्रम्प पर महाभियोग चलाया जा सकता है। चूंकि महाभियोग एक आपराधिक प्रक्रिया की तुलना में एक राजनीतिक प्रक्रिया है, इसलिए ट्रम्प को यदि आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत सफल रूप से दोषी ठहराया जाता है तो पिछली बार सीनेट में दोषी ठहराए जाने के विपरीत उन पर सदन पर एक बार फिर से महाभियोग चलाना आसान होगा।

यह ध्यान देने योग्य है कि अमेरिका के संविधान में ऐसा कुछ नहीं है जो यह कहता हो तो कि यदि छोड़ने के बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता।

ट्रम्प से बदला लेने के लिए यह कार्यवाही व्यर्थ नहीं बल्कि एक रोग निरोधक उपाय होगा। संविधान में महाभियोग और दोषी ठहराए जाने के लिए जो सजा निर्धारित है, उसमें किसी अमेरिका में सम्मान का पद पाने, ट्रस्ट या लाभ का पद पाने के अयोग्य घोषित होना शामिल है। अन्य शब्दों में महाभियोग चलाए गए या दोषी ठहराए गए ट्रम्प राष्ट्रपति चुनाव फिर से कभी नहीं लड़ सकेंगे।

'माफीवीर'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 जून। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट किया कि पूरे देश के आंदोलनरत युवाओं, जो ''अग्निवीर'' बनने से इनकार कर रहे हैं, के दबाव के परिणामस्वरूप, प्रधानमंत्री मोदी को ''माफी वीर'' बनते हुये, ''अग्निपथ'' योजना वापस लेनी पड़ेगी, ठीक वैसे ही, जैसे किसानों के एक साल के आंदोलन

- **अग्निपथ योजना के खिलाफ देशभर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में राहुल गांधी ने प्र.मंत्री मोदी पर कटाक्ष किया।**

के दबाव के बाद, उन्होंने काले कृषि कानून वापस लिये थे।

उन्होंने कहा कि मोदी की भाजपा सरकार पिछले आठ साल से ''जय जवान, जय किसान'' के मूल्यों का लगातार अपमान करती आ रही है।

राहुल गांधी कि बहिन तथा कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने 29 मार्च 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर सैनिकों की भर्ती करने का आग्रह किया था। उन्होंने ट्वीट किया था कि वे उन ग्रामीण युवाओं के दर्द को समझें, जो सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)